सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-102
16/02/2017

सड़क निर्माण में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा– मुख्यमंत्री

पटना, 16 फरवरी 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण कार्य विभाग के 1571.65 करोड़ के 947 पथों एवं 38 पुलों का शिलान्यास, 895.72 करोड़ रूपये के 554 पथों एवं 42 पुलिों का कार्यारंभ एवं 2305.73 करोड़ रूपये के 2325 पथों एवं 36 पुलों का रिमोट से उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सबसे पहले ग्रामीण कार्य विभाग को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का उदघाटन भी कराया है और उसके साथ–साथ जो स्वीकृत योजनायें हैं उनका शिलान्यास भी कराया है और पूर्व में जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ उनका अब कार्य आरंभ भी कराया है। हमलोगों ने सड़कों के निर्माण पर प्रारंभ से ही जोर दिया है। जो बड़ी सड़कें हैं वे पथ निर्माण विभाग के अधीन हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन हैं। प्रारंभ से ही हमलोगों ने यह कोशिश की है कि हम हर गॉव को पक्की सड़क से सम्पर्कता प्रदान कर दें ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा मिल जाय। हमारे यहॉ कृषि की महत्ता है और आज भी जो 2011 का जनगणना रिपोर्ट है उसके मुताबिक लगभग 89 प्रतिशत लोग गॉव में निवास करते हैं। और जो गॉव में निवास करते हैं उनका मुख्य कार्य खेती से जुड़ा हुआ है। हमारे बिहार में अभी भी 76 प्रतिशत लोग आजीविका के लिये कृषि पर आधारित हैं। पहले यह देखा जाता था कि किसान मेहनत करके फसल उपजाते थे लेकिन आवागमन की असुविधा के कारण उन्हें उचित कीमत नहीं मिल पाती थी। सम्पर्कता प्रदान करने का सबसे बड़ा लाभ यह हो रहा है कि अब गॉव के अन्दर विभिन्न जगहों पर अलग–अलग फसलों का उत्पादन लोग कर रहे हैं। उन्हें सम्पर्कता मिल गयी है और वे अपने फसल की बाजार कीमत प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में जो हमारी भूमि है उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, कुछ पहाड़ी इलाकों अगर छोड़ दिया जाय तो बाकी जितने इलाके हैं उन सभी इलाकों की उरर्वा शक्ति बहुत है और किसी भी चीज की खेती कर सकते हैं। चाहे वो अन्न की खेती हो, दलहन हो, तेलहन हो, सब्जी हो या फल हो। इन सब चीजों को उपजा सकते हैं। लेकिन इसका लाभ लोग नहीं उठा पाते थे। क्योंकि अगर कोई खेती करें और उसकी जो भी उपज हुयी उसकों लेजाने के लिये आवागमन का साधन नहीं हो तो वैसी स्थिति में जो आवागमन का खर्च था वही इतना ज्यादा था कि फिर उन्हें उसकी कीमत नहीं मिल पाती थी। तो बहुत सारी जगहों पर जो फसल उपजा सकते थे जिसमें ज्यादा उनको मिलता वैसी फसलों को उपजा नहीं पाते थे। और दूसरी बात है कि हर किसी को अधिकार है कि बुनियादी सुविधा मिले। तो इसलिये हमलोगों ने गॉव को सड़क से जोड़ने की योजना बनायी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी और उसका पहला नक्शा था कि एक हजार की आबादी वाले जितने बसावट है, गॉव हैं उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जायेगा। हमलोगों ने काम संभाला तो इस बात को महसूस किया कि हमारा ग्रामीण कार्य विभाग सक्षम है इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये।

तो हमने सन 2007–08 के करीब ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य प्रारंभ किया। हमलोगों ने उसी समय निर्णय लिया कि जो 500 आबादी तक के गॉव हैं उनको भी जोड़ा जाना चाहिये। राज्य सरकार की एक अपनी योजना बनायी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और उसमें तय किया की जो 500 से 999 आबादी वाले बसावट हैं उनको इस योजना के अन्तर्गत सड़क सम्पर्कता प्रदान की जायेगी और उसपर काफी काम हुआ। इस बीच केन्द्र सरकार ने यह योजना बनायी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत हम 500 आबादी वाले गॉवों को लेंगे। तो हमलागों ने यह भी तय किया कि जो 500 की आबादी के नीचे और ढाई सौ आबादी तक के जो बसावट हैं उनकों हम अपनी राज्य की योजना से जोड़ें। इसी बीच में केन्द्र सरकार ने यह भी फैसला किया कि जो आई0ए0पी0 डिस्ट्रिक्ट हैं यानी जिनको वो नक्सल प्रभावित मानते हैं। ऐसे 11 जिले बिहार में चिन्हित हैं। वहॉ के बारे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत यह तय किया गया कि 250 आबादी वाले तक के बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा। तो हमलोगों ने देखा कि जो हमारे बाकी के 27 जिले हैं वे वंचित न रह जायें तो शेष 27 जिलों के लिये हमलोगों ने अपनी योजना बनायी मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना और इसके अन्तर्गत 250 आबादी से लेकर 499 आबादी तक के जितने बसावट हैं सबका एक कोर नेटवर्क बनाया गया और उसपर काम प्रारंभ कर दिया। इसके लिये राज्य सरकार के पास जो संसाधन थे हमलोगों ने लगाया। इस कार्य के लिये बहुत पैसे की जरूरत थी और राज्य सरकार के बजट से इस काम को पूरा करने में बहुत समय लगता। तो हमलोगों ने विश्व बैंक से बातचीत की और विश्व बैंक इस बात के लिये सहमत हो गया। और मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत 5 हजार किलोमीटर सड़क बनाने के लिये विश्व बैंक ने अपनी सहमति दी और विश्व बैंक से ऋण लेकर हमलोगों ने राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत इस कार्य को आरंभ किया। जो ऋण विश्व बैंक से लिया जाता हैं उसमें 70 प्रतिशत विश्व बैंक देता है और 30 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होता है। तो 5 हजार किलोमीटर के लिये 70 प्रतिशत विश्व बैंक से लेकर और उसमें 30 प्रतिशत अपनी ओर से लगाकर इस योजना पर कार्य आरंभ किया गया। उसके बाद हुया कि केवल 5 हजार किलोमीटर से तो काम नहीं चलेगा। तो उसके लिये हमलागों ने नया बैंक ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में अप्लाई किया हुआ है। अभी ब्रिक्स बैंक द्वारा उसपर निर्णय नहीं हुआ है लेकिन हमलोगों ने अपनी ओर से सारी औपचारिक्तायें पूरी कर ली हैं।

आज मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत कई योजनाओं का शिलान्यास और कई योजनाओं का उदघाटन भी किया गया है। इसके अलावे सात निश्चय के अन्तर्गत जो बसावट बचे हैं उनका सर्वेक्षण करके उनको भी शामिल किया गया है। हमलोगों ने ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना को भी सात निश्चय के अन्तर्गत इसको भी क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। सम्पर्क सड़ के लिये बनयी गयी सूची को सभी जन प्रतिनिधि को दिया जाय और उनसे फीडबैक लिया जाय कि कोई बसावट छूट तो नहीं गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे खुशी है कि इस योजना को पूरे बिहार में लागू करने के लिये ग्रामीण कार्य विभाग ने ठोस कदम उठाया है। और आज मैंने देखा कि इन्होंने नयी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना शुरू किया है। नयी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ सड़कों में इन्होंने किया है और उसकी उपयोगिता और बेहतर नतीजे दिखेंगे तो अन्य जगहों पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तमाल करेंगे। जो नयी टेक्नोलॉजी देश में देश से बाहर सड़क निर्माण के लिये आ रही हैं उन सभी का अध्ययन करके हमारे मिट्टी के जो अनुरूप हो, हमारी जरूरतों के अनुरूप हो उसको शामिल किया जाता है। इस के लिये ग्रामीण कार्य विभाग को मैं बधाई देता हूँ और हमारे इंजीनियर्स को विशेष रूप से। नयी टक्नोलॉजी के उपयोग से सड़क

निर्माण में हमारा कॉस्ट 30 प्रतिशत घट रहा है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर एक किलो मीटर सड़क बनाने में सिमेंट, कंक्रीट का अनावश्यक इस्तेमाल कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के जरिये उसकी मात्रा घट जाये और उसकी मजबूती उसी प्रकार बनी रहे तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिये। उन्होंने कहा कि हम 100 तक की आबादी वाले हर बसावट को पक्की सड़क से जोड़ना चाहते हैं और सात निश्चय के अन्तर्गत हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण करना चाहते हैं। अभी निश्चय यात्रा के अन्तर्गत हर जिले के किसी न किसी गॉव में जाकर मैंने योजनाओं के क्रियान्वयन को देखा है। जब गॉव में पक्की गली बनने लगती है और ड्रेनेज और नाली का निर्माण होता है तो गॉव के लोगों की खुशी देखने लायक होती है और उनको अगर नल का पानी मिल जाय पीने के लिये, बिजली मिल जाये तो वे शहर की तरफ क्यों देखेंगे। गॉव के अंदर योजनाओं के क्रियान्वयन का सकारात्मक प्रभाव है। लोग जब जानते हैं कि हमारे लिये सब काम हो रहा है तो लोगों में उत्साह बढ़ता है। हर मनुष्य के अन्दर ताकत है, कई बार होता है कि निराशा में वह अपनी ताकत को पहचान नहीं पाता है और उसका उपयोग नहीं करता है। इस तरह का वातावरण बनाने से उनके मन की आशा इतनी जगती है कि फिर वह अपनी ताकत को पहचानता है और अपनी उर्जा और अपनी शक्ति के अनुरूप कुछ करना चाहता है। इसी से तो विकास होगा। विकास के लिये हम नहीं मानते कि चंद फैक्ट्रियॉ लग जायें तो विकास हो जायेगा, विकास के लिये तो हर आदमी की उत्पादन क्षमता का हमें उपयोग करना है। इससे जो विकास होगा वह स्थायी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारा डबल डिजिट ग्रोथ रेट है। बहुत लोग इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरू में जब हमने देखा कि 12 प्रतिशत से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो हमने स्कूल बनाने, बच्चों के लिये अतिरिक्त वर्ग कक्ष आदि सब बनाने का निर्णय लिया। उस वक्त लगा कि इतना स्कूल बनाने का कार्य कौन करेगा। तो हमलोगों ने निर्णय लिया कि सभी स्कूलों में बनाये गये शिक्षा समिति को ही पैसे दे देंगे। उपरोक्त जगह के अनुरूप भवन का डिजाइन बनाकर उसकी स्वीकृति दे दिया जायेगा। शिक्षा समिति द्वारा विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य किया जायेगा। इस निर्णय के पश्चात हर कस्बों में भवन निर्माण समाग्री बिकने लगीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल भवन निर्माण का कार्य विकेन्द्रित तरीके से किया गया। आज उसी प्रकार सात निश्चय योजनांतर्गत हर घर नल का जल, हर गॉव में पक्की नाली एवं सड़क आदि का निर्माण कार्य विकेन्द्रित तरह से किया जा रहा है। वार्ड स्तर पर वार्ड विकास समिति बनायी गयी है उसके माध्यम से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जरूरतों के अनुसार निर्माण का कार्य करेंगे। अपने सांसद के रूप में कार्यकाल का उदाहरण देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उस वक्त लोगों से मिलने के लिये क्षेत्र में जाना होता था तो पैदल ही जाते थे। आज जहॉ भी जाना है गाड़ी से जा सकते हैं, यह कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सडकों का मेंटेनेंस होना चाहिये, जो सड़कें बनायी हैं तो उनको मेंटेन भी रखें। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में शुरू से यह ख्याल रखा जाय कि सड़क का निर्माण अच्छी क्वालिटी का हो रहा हो। क्वालिटी के साथा कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी अभियंताओं से कहा कि अपने कार्यों को ठीक ढंग से कीजिये। आत्मसंतोष तब होगा जब आप अपने कार्य से संतुष्ट होंगे। उन्होंने कहा कि नयी टेक्नोलॉजी को अपनाना अच्छी रणनिति है। उन्होंने कहा कि योजना के लिये धन उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है, लेकिन योजना को गुणवता के साथ क्रियान्वित करना आपका दायित्व है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य मंत्री श्री शैलेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री

चंचल कुमार, सचिव ग्रामीण कार्य विभाग श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता श्री अनिल कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंतागण उपस्थित थे।

******